

प्रेषक,

भास्करानन्द,  
सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,  
अल्मोड़ा।

राजस्व अनुभाग-2

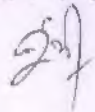
देहरादून: दिनांक: 11 मार्च, 2015

विषय:-जनपद अल्मोड़ा में गोलूछिना-गल्ली-बस्यूरा-गोविन्दपुर मोटरमार्ग के निर्माण हेतु कुल 0.426 है० भूमि लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन को निःशुल्क हस्तान्तरित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-3231/ग्यारह-09/2013-14 दि०-01.03.2014 तथा आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र सं०-5384/रा०प०-भू०हस्ता० (गोलू-गोवि० मो०मार्ग)/2015 दि०-09.01.2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, ग्राम चिनौणा, प०क्षे० गोविन्दपुर, तहसील एवं जनपद अल्मोड़ा के नॉन जेड०ए० खाता खतौनी सं०-72 की श्रेणी 9(3)ड बंजर काबिल आबाद के पैमाइशी खसरा सं०-383 मध्ये 0.010 है० एवं ख०खा०सं०-72 की श्रेणी 10(2) रास्ता के खसरा सं०-382 मध्ये 0.003 है० तथा ख०सं०-384 मध्ये 0.003 है० अर्थात् उक्त गांव की कुल 0.016 है०, राजस्व ग्राम गल्ली बस्यूरा के नॉन जेड०ए० ख०खा०सं०-78 की श्रेणी 9(3)ड बंजर काबिल आबाद के पैमाइशी खसरा सं०-495 म० 0.054 है०, 491 म० 0.004 है०, 47 म० 0.025 है०, 479 म० 0.025 है०, 6601 म० 0.018 है०, 7732 म० 0.018 है०, 7794 म० 0.023 है०, 7776 म० 0.019 है०, 7794 म० 0.023 है०, 7621 म० 0.023 है० एवं 7849 म० 0.021 है०, ख०खा०सं०-84 श्रेणी 10(1) जलमग्न भूमि के खसरा सं०-494 की 0.001 है०, 6294 की 0.019 है०, 6325 की 0.009 है०, 6441 की 0.001 है० एवं 6440 की 0.003 है० तथा ख०खा०सं०-93 श्रेणी 10(2) रास्ता के खसरा सं०-851 की 0.001 है०, 996 की 0.001 है०, 2158 की 0.003 है०, 6365 की 0.003 है०, 7777 की 0.010 है० इस प्रकार उक्त गांव की कुल 0.304 है० भूमि तथा ग्राम बडला के नॉन जेड०ए० खाता खतौनी सं०-23 की श्रेणी 9(3)ड बंजर काबिल आबाद के पैमाइशी खसरा सं०-429 म० 0.005 है०, 494 म० 0.010 है०, 427 म० 0.013 है०, 425 म० 0.021 है०, 408 म० 0.031 है०, 85 म० 0.003 है०, 445 म० 0.009 है०, 2607 म० 0.009 है० तथा ख०खा०सं०-25 की श्रेणी 10(1) जलमग्न भूमि नाला के खेत सं०-410 की 0.005 है० इस प्रकार उक्त ग्राम की कुल 0.106 है० भूमि अर्थात् उपरोक्त तीनों ग्रामों की कुल 0.426 है० भूमि को वित्त अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-260/वित्त अनुभाग-3/2002 दिनांक 15.02.2002 के प्राविधानों के अधीन तथा लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन के विभागीय परामर्श/अनापत्ति के कम में निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन को निःशुल्क हस्तान्तरित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

- 1- भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत न हो।
- 2- जिस परियोजना के लिए भूमि हस्तान्तरित की जा रही है वह एक अनुमोदित परियोजना हो और उसके लिए शासन से सहमति प्राप्त हो चुकी हो।
- 3- हस्तान्तरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग की जाये तो उसके लिये मूल विभाग से पुनः अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
- 4- यदि भूमि की आवश्यकता न हो या 3 वर्षों तक हस्तान्तरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिए उपयोग में नहीं लायी जाती है तो वह मूल विभाग में स्वतः ही निहित हो जायेगी। .....2





- 5- जिस प्रयोजन हेतु भूमि हस्तान्तरित की जा रही है उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु किसी अन्य व्यक्ति, संस्था, समिति अथवा विभाग आदि को मूल विभाग की सहमति के बिना भूमि हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।
- 6- जिस प्रयोजन हेतु भूमि आवंटित की जा रही है उसकी पूर्ति के उपरान्त यदि भूमि अवशेष पड़ी रहती है, तो मूल विभाग को उसे वापस लेने का अधिकार होगा।
- 7- प्रश्नगत भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधान लागू होने के कारण भारत सरकार की पूर्वानुमति मिलने के पश्चात ही वास्तविक हस्तांतरण किया जाना जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
- 8- प्रश्नगत नॉन जेड0ए0 भूमि आवंटन के पूर्व जमींदारी विनाश एवं भू-सुधार अधिनियम की धारा-132 व इसके समकक्ष एवं अन्य सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
- 9- इस संबंध में सिविल अपील संख्या-1132/2011(एस0एल0पी0)/(सी) संख्या- 3109/2011 श्री जगपाल सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य तथा सिविल अपील सं0-436/2011, /SLP(C) NO. 20203/2007 झारखण्ड राज्य व अन्य बनाम पाकुर जागरण मंच व अन्य में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश दि0-जनवरी, 2011 में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं अन्य संगत निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 10- आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तों बिन्दु संख्या-01 से 09 में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नहीं होगा।

कृपया इस संबंध में नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में जिला स्तर से निर्गत आदेश एवं इस शासनादेश की शर्तों के अनुपालन स्थिति से यथा समय शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(भास्करानन्द)  
सचिव।

पृ0प0संख्या- 150 /समदिनांकित/2015

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 3- आयुक्त, कुमाऊं मण्डल, नैनीताल।
- 4- निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संतोष बडोनी)  
उप सचिव।